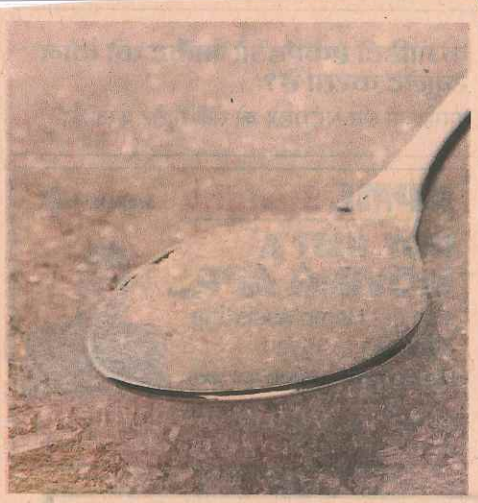

चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने हटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी

[माधवी सैली & जयश्री भोसले | नई दिल्ली & पुणे]

चीनी का निर्यात बढ़ाने और देश में इसकी कीमतों में वृद्धि के लिए सरकार ने मंगलवार को चीनी पर 20 पर्सेंट की एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी। हालांकि, इसका चीनी की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार के इंसेंटिव के बिना निर्यात करना मुश्किल होगा। देश में चीनी का सरप्लस उत्पादन होने का अनुमान है। फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने से एक्सपोर्ट की मौजूदा वॉल्यूम पर 75 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का नुकसान होगा। शुगर ब्रोकर अभिजीत घोरपडे ने बताया, 'स्थिति लगातार खराब हो रही है। चीनी पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने के फैसले का मंगलवार को कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा।' उनका कहना था कि अतिरिक्त चीनी को देश से बाहर भेजने की जरूरत है।

20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म, इसका चीनी की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार के इंसेंटिव के बिना निर्यात करना मुश्किल होगा

चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने 2017-18 में चीनी के उत्पादन का अनुमान बढ़ाकर 2.95 करोड़ टन कर दिया है। इस्मा ने पहले 2.61 करोड़ टन के उत्पादन की उम्मीद जताई थी। 2017-18 के क्लोजिंग स्टॉक को कम करने के लिए शुगर इंडस्ट्री अक्टूबर 2018 तक 15-20 लाख टन चीनी का निर्यात करने की योजना बनाई है।

अक्टूबर में ही चीनी का नया वर्ष शुरू होता है। इस्मा के वाइस प्रेसिडेंट, रोहित पवार ने कहा, 'एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने का चीनी की कीमतों पर मामूली असर हुआ है, लेकिन निर्यात को प्रोत्साहन देने के मकसद से हम इसे सरकार का एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। ब्राजील में चीनी का उत्पादन घटने का अनुमान है और ऐसे में भारत के लिए कच्ची चीनी का निर्यात करने का अच्छा मौका है।' 2017-18 में देश में लगभग 3 करोड़ टन और 2018-19 में इससे कुछ अधिक उत्पादन होने की उम्मीद है।

पवार ने कहा कि अगर सरकार मिलों को इंसेंटिव देने को लेकर जल्द फैसला करती है तो मिलें कच्ची चीनी के उत्पादन की तैयारी कर सकती हैं। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि अगर इंसेंटिव दिया जाए तो ब्राजील से चीनी का आयात कर उसकी प्रोसेसिंग के बाद दोबारा निर्यात करने वाली मिलें देश की कच्ची चीनी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार बांग्लादेश को ब्राजील के बजाय भारत से कच्ची चीनी खरीदने के लिए आश्वस्त करे। इसके अलावा इंडस्ट्री श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ देशों को भी निर्यात करना चाहती है। सरकार ने पिछले महीने चीनी पर इम्पोर्ट ड्यूटी दोगुनी बढ़ाकर 100 पर्सेंट कर दी थी।

The Economic Times
21/3/18